



दैनिक

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रामपुर, रायबरेली, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित ।

दैनिक बुद्ध का संदेश

8795951917, 9415163471

@budhakasandesh

budhakasandeshnews@gmail.com

www.budhakasandesh.com

उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

एल्युमिनियम बनाम स्टेनलेस स्टील ...8

सिद्धार्थनगर

शनिवार ,11 जुलाई 2026

वर्ष: 13 अंक : 209 पृष्ठ: 8

आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

एक विश्वास....

सम्पादक : राजेश शर्मा

अयोध्या में सपा-कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी मैंने पुलिस पर भरोसा किया, उन्होंने ही...

पूछा- हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों कराया था?

अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती रही हैं और जो लोग अब आस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग अब भगवान राम और आस्था की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही हाल ही में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। अपनी आलोचना को और तेज करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा अयोध्या के विकास का विरोध किया



है और उन प्रोजेक्ट्स का मजाक भी उड़ाया है जो अब हकीकत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। समाजवादी पार्टी के नेता इस विचार का मजाक उड़ाते थे। आज अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वे इसके

नाम से खुश नहीं हैं क्योंकि इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने की कथित घटना का जिक्र करते हुए, आदित्यनाथ ने सवाल किया कि ऐसी हरकत की इजाजत क्यों दी गई और इसकी तुलना पूजा-पाठ की दूसरी जगहों पर होने वाली धार्मिक गतिविधियों से की। उन्होंने कहा कि जरा सोचिएकृक्या कोई कभी जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है? क्या कोई सरकार ऐसा करवा सकती है? क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ऐसा करवा सकती है? अगर वे ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर इस काम की इजाजत क्यों दी गई? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर ऐसा क्यों किया गया?

सीएम विजय ने कसूर त्रासदी के घाव को किया याद, बोले- यह दर्द कभी नहीं भूलेगे

करूर में मची भगदड़, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी और जिसका असर राज्य विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा था, उसके नौ महीने बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय श्रुक्वार को शहर लौटे। उन्होंने इस त्रासदी में अपनी भूमिका का बचाव किया, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और पिछली कड़ज सरकार पर तीखा हमला किया। मुख्यमंत्री के तौर पर करूर के अपने पहले दौर पर पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आयोजित एक सभा को



संबोधित करते हुए, विजय ने भावुक होकर उस त्रासदी को याद किया और कहा कि उस नुकसान का बोझ आज भी उनके मन पर भारी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार करूर के दौरे

पर आए उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, मानसिक रूप से कुछ ऐसे घाव और चोटें होती हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम कई तरह की चोटों और घावों से उबरकर ही यहां तक घप्पहुंचे हैं। लेकिन इन सबसे बुरा, वह घाव और दर्द जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, वह करूर की घटना थी। विजय ने कहा कि पिछले साल करूर का उनका दौरा जटिल के लोगों तक पहुंचने और उनकी समस्याओं के बारे में आवाज उठाने

का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि अरियालुर में एक मीटिंग खत्म करने के बाद पेरम्बलुर पुलिस ने उन्हें वहाँ जमा भारी भीड़ के बारे में आगाह किया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बताया गया था कि देर हो रही है और उन्हें वहाँ नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। जब पुलिस हमें कुछ कहती है, तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ती है, है ना? साथ ही, पेरम्बलुर के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम भारी मन से वापस लौट आए।

जिसके पास लाइसेंस, सिर्फ वही सिक्योरिटी एजेंसी करेगी काम

अमित शाह ने बंदरगाहों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बंदरगाहों की सुरक्षा में केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसी ही काम पर लगाने पर जोर दिया।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ बैठक कर पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के गठन में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए शाह ने बंदरगाहों पर सिर्फ सीआईएसएफ द्वारा प्रशिक्षित निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की जरूरत बताई। इन सुरक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण

के लिए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की मौजूदा आधारभूत संरचना का इस्तेमाल किया जा सकता है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार तटीय सुरक्षा को अमेध बनाने के लिए कृतसंकल्प है। अमित शाह ने दिए निर्देश

देश में विकास की तेज रफ्तार और उसी के अनुसार बंदरगाहों पर बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अमित शाह ने उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत बताई। उन्होंने



कहा कि पत्तन सुरक्षा ब्यूरो में तैनात किए जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का एक डेटाबेस बनाया जाए। पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के तहत आने वाले सभी बंदरगाहों पर कंटेनर स्कैनिंग की व्यवस्था

हो। उन्होंने सीआईएसएफ को देश के बड़े बंदरगाहों, जैसे विशाखापत्तनम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट पर जाकर पत्तन सुरक्षा ब्यूरो को सौंपी जाने वाली सुरक्षा का ट्रायल करने को कहा। हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए बनाए ब्यूरो आफ सिविल एविएशन की तर्ज पर बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत पत्तन सुरक्षा ब्यूरो का गठन किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक

महानिदेशक करेगा और यह पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। पत्तन सुरक्षा ब्यूरो जहाजों और अपनी पार्टी (अवामी लीग) पर प्रतिबध डोल रही शेख हसीना ने कहा कि वे अपने देश में कोर्ट के सामने खुद को सरेंड़ कर यह देखना चाहती हैं कि बांग्लादेश की सरकार अपने सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के साथ कैसा व्यवहार करती है। दक्षिण एशियाई देश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना ने कहा कि वह और उनकी अवामी लीग के सदस्य स्वेच्छा से उस देश लौटना चाहते हैं, जिसे वे दो साल पहले छोड़कर भाग गई थी।

कांग्रेस के साथ विलय की खबरों पर सुप्रिया सुले का विराम

कहा- सहयोगी के तौर पर मिलकर काम करते रहेंगे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कांग्रेस में अपनी पार्टी के विलय की तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों दलों के बीच विलय को लेकर न तो कोई बातचीत हुई है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सामने आया है। सुले ने कहा कि दोनों दल एक मजबूत सहयोगी के रूप में भविष्य में भी साथ मिलकर काम करते रहेंगे। सुप्रिया सुले ने पुणे में संवाददाताओं से बातचीत

के दौरान कहा कि राकांपा (शप) किसी भी तरह की विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है और न ही उनकी पार्टी ने विलय को लेकर कोई पहल की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) और राष्ट्रीय स्तर पर रईडियाइंग गठबंधन के घटक दलों के रूप में दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल है और वे सहयोगी के रूप में हमेशा साथ रहेंगे। दोनों दलों के बीच मजबूत और सौहार्दपूर्ण रिश्तों का

जिक्र करते हुए सुले ने बताया कि वे राजनीतिक मुद्दों पर नियमित रूप से एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के समय वह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से मिलकर महाराष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करती हैं। इसके अलावा, वह राज्य के विभिन्न विषयों पर राहुल गांधी के साथ भी लगातार विचार-विमर्श करती हैं और संसद की कई संयुक्त समितियों में दोनों



दल साथ मिलकर काम करते हैं। सुले ने दोनों परिवारों के बीच के करीबी रिश्तों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले महीने मुंबई में उनकी बेटी रेवती और उद्योगपति सारंग लखानी के विवाह समारोह

में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और नवदंपति को अपना आशीर्वाद दिया था। उन्होंने दोहराया कि सहयोगी दल के रूप में राकांपा (शप) और कांग्रेस पहले भी साथ थे आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। गौरतलब है कि सुप्रिया सुले के पिता और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने वर्ष 1999 में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठन किया था। जुलाई 2023 में पार्टी में उस समय विभाजन हो गया था जब तत्कालीन

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न मिला, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट राकांपा (शप) के नाम से जाना जाने लगा। पिछले सप्ताह कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कांग्रेस से अलग हुए क्षेत्रीय दलों से अपनी मूल पार्टी में लौटने की अपील की थी ताकि वैचारिक प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला मजबूती से किया जा सके।

राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी की जांच संबंधी याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। देश की शीर्ष अदालत आगामी 13 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति ज्योत्सनाका बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ सोमवार को अदालत की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस मामले में तीन अलग-अलग

याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से एक याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने और राम मंदिर का प्रबंधन देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (केग) से ऑडिट कराने का अनुरोध किया है। दूसरी याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है, जिसमें इसी तरह के अनुरोध किए गए हैं। वहीं, तीसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने दायर की



है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ-साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। इससे पहले न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन

विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज, प्रशासन और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा

गठित एसआईटी ने बिना कोई प्राथमिकी या नियमित आपराधिक मामला दर्ज किए ही जांच शुरू कर दी थी। उनका तर्क है कि स्वतंत्र रूप से आरोपों का सत्यापन एक पेशेवर जांच एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए जिसके पास जटिल वित्तीय और आपराधिक मामलों की जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और संसाधन उपलब्ध हों। याचिका में कहा गया है कि इस जांच से जनता का भरोसा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ संभावित संज्ञेय अपराधों तक सीमित नहीं है बल्कि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाएं जुड़ी हैं।

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबों में किए गए बदलावों को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। गहलोत ने सरकार से इस कदम को संकीर्ण मानसिकता का सूत्र बताया है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जिस विवाधारा का देश के स्वाधीनता आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं रहा और जिसने देश की आजादी की लड़ाई में कभी कोई योगदान



अहंकार में डूबी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही ताकतें आज देश के इतिहास और उसके तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि एनसीईआरटी की कक्षा आठ की किताबों में हाल ही में किए गए बदलाव इसी संकीर्ण सोच का नतीजा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताते हुए कहा कि वह अपनी कमियों को छिपाने के लिए गलत जनमत तैयार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को सुधारने के बजाय हमारे महान पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों पर छींटाकशी कर रही है और एक गलत नैरेटिव (विमर्श) तैयार करने में जुटी है।

भैरिज हाल में युवक का शव फंदे से लटका मिला, पत्नी को भेजा था अंतिम वीडियो

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र स्थित भैसाही गांव के मेजबान गार्डन भैरिज हॉल में गुरुवार दोपहर एक 27 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी है। मृतक की पहचान सचिन विश्वकर्मा (27 वर्ष) पुत्र अमरनाथ विश्वकर्मा, निवासी शंकरगढ़ गांव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सचिन ने करीब पांच वर्ष पहले अंशु विश्वकर्मा से प्रेम विवाह किया था। दंपति की तीन वर्षीय पुत्री बनिष्का है। परिवार पिछले

लगभग दो महीने से मेजबान गार्डन भैरिज हॉल में किराये पर रह रहा



था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के समय पत्नी बढ़या चौराहे पर बाजार गई हुई थी। इसी दौरान सचिन ने कथित तौर पर गले में रस्सी डालकर एक वीडियो पत्नी को भेजा, जिसमें उसने अपनी जान

देने की बात कही। वीडियो देखते ही पत्नी तत्काल भैरिज हॉल पहुंची, लेकिन तब तक सचिन ऊपर की मंजिल के एक कमरे में पंखे से नायलॉन की रस्सी के सहारे लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर मिश्रौलिया थाना प्रभारी मनोज कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाई की जाएगी।

खेसरहा में लाखों से बना सामुदायिक शौचालय बना शोपीस: ग्रामीणों को नहीं मिल रही सुविधा

दैनिक बुद्ध का संदेश
खेसरहा। खेसरहा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायत बनौली में लाखों रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय देखरेख और संचालन के अभाव में अनुपयोगी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यह शौचालय केवल शोपीस बनकर रह गया है, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, इस सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्व ग्राम प्रधान के कार्यकाल में हुआ था। हालांकि, निर्माण के बाद इसकी नियमित देखरेख के लिए किसी केयरटेकर की नियुक्ति नहीं की गई। इसी कारण शौचालय का संचालन ठप हो

गया है और ग्रामीण इसका लाभ

होने के बावजूद यह सुविधा बंद

वेद प्रकाश ने बताया कि शौचालय बनने के बाद कुछ समय तक सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह उपयोग में नहीं है। बबलू का कहना है कि शौचालय बंद होने के कारण लोगों को अन्य विकल्प तलाशने पड़ते हैं। हर्षित ने कहा कि यदि नियमित सफाई और देखरेख होती, तो यह ग्रामीणों के लिए उपयोगी साबित होता। रीता ने बताया कि महिलाओं को स्वच्छ शौचालय की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जिससे सरकारी धन का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। गांव के



नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च

बिजली बिलों के विरोध में भिनगा में किसानों का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम

दैनिक बुद्ध का संदेश
भिनगा / श्रावस्ती। बिजली बिलों में कथित गड़बड़ी के विरोध में भारतीय किसान



जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई गांवों में बिजली के पोल और तार तक नहीं लगे हैं, फिर भी उपभोक्ताओं को भारी-भरकम बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। किसानों ने गलत बिलिंग और मीटर संबंधी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाई की मांग की। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक्सईएन (म्छ) भिनगा को अपने बीच बैठकर विरोध जताया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह पूरा मामला श्रावस्ती जिला मुख्यालय स्थित भिनगा बिजली पावर हाउस का है। भारी बिजली बिलों पर भड़के किसान, भिनगा में सड़क जाम बिजली विभाग के खिलाफ किसानों का हल्लाबोल भिनगा में ट्डा का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक गलत बिजली बिलों पर किसानों का विरोध, जांच की मांग की है।

सोनौली का जाम हुआ विकारलरू ट्रकों के बीच फंसी स्कूल बस, मासूमों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनौली / महाराजगंज। भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनौली



कस्बे में शुक्रवार को एक बार फिर भीषण जाम ने आमजन के साथ-साथ स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दीं। जाम इतना विकराल था कि स्कूल बसें भी घंटों तक ट्रकों और भारी वाहनों के बीच फंसी रहीं। वायरल हो रही तस्वीर में एक स्कूल बस, जेसीबी और मालवाहक ट्रक चौराहे पर जाम में फंसे दिखाई दे रहे हैं, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को लंबे समय तक जाम में इंतजार करना पड़ा। कई अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा कि भारी वाहनों के बीच फंसी स्कूल बसें बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। बरसात और उमस के मौसम में बसों के भीतर बैठे बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सोनौली में ट्रकों की अव्यवस्थित आवाजाही, ओवरलोड वाहनों का दबाव और प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन की कमी के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, मरीजों और सीमा पार आने-जाने वाले यात्रियों को उठानी पड़ रही है।

खेसरहा में लाखों का आरआरसी सेंटर बना शोपीस: मरवटिया बाजार में ठोस कचरे का नहीं हुआ वैज्ञानिक निस्तारण

दैनिक बुद्ध का संदेश
खे सरहा। खे सरहा

का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों

बाद गांव में सफाई व्यवस्था सुधरने की उम्मीद थी। हालांकि,

विकासखंड स्थित मरवटिया बाजार ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपये की लागत से बना रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी) शोपीस बनकर रह गया है। ठोस कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के उद्देश्य से निर्मित यह केंद्र आज तक संचालित नहीं हो सका है। केंद्र भवन पर न तो पेंटिंग कराई गई है और न ही इसका नाम और उद्देश्य अंकित है। ग्रामीणों के अनुसार, यह योजना उनके लिए श्हाथी के दांत दिखाने के और, खाने के औरश् जैसी साबित हो रही है, क्योंकि इसका वास्तविक लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों



की उदासीनता के कारण यह योजना धरातल पर विफल हो गई है। गांव में आज भी कचरा इधर-उधर फेंका जा रहा है, जबकि उसके निस्तारण के लिए बना आरआरसी सेंटर वीरान पड़ा है। ग्रामीण साहिल, चंद्र प्रकाश, राम प्रसाद और सविता ने बताया कि आरआरसी सेंटर बनने के

आज तक यहां कचरा एकत्र करने या उसके वैज्ञानिक निस्तारण की कोई व्यवस्था शुरु नहीं हुई है, जिससे सरकारी धन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्राम प्रधान धिमलावती के प्रतिनिधि धर्मेंद्र जायसवाल ने कहा कि केंद्र को पूरी तरह संचालित कराने और आवश्यक व्यवस्थाएं शुरु कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से मांग की जाएगी, ताकि इसका मूल उद्देश्य पूरा हो सके। लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई इस स्वच्छता परियोजना का उपयोग न होने से सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मखाना की उन्नत खेती का प्रशिक्षण लेने दरभंगा जाएंगे कुशीनगर के किसान

कुशीनगर। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण, आत्मा के गवर्निंग बोर्ड तथा जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की विभिन्न योजनाओं की एकजीक्यूटिव कमेटी की वित्तीय वर्ष 2026-27 की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि एवं रस्बंध विभागों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करने पर जोर दिया गया। बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं प्रगति आख्या प्रस्तुत किए जाने से हुई इसके उपरान्त चूड़ा निगंत्रण अभियान फार्मर

रजिस्ट्री एवं विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश श्री अन्न, मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, मिशन फॉर आत्म निर्भरता इन पल्सेस तथा नेशनल मिशन ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी सहित सभी योजनाओं का लाभ जनपद के प्रत्येक विकास खंड के किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से युवा कृषकों को कृषि आ

गारित उद्यमों से जोड़ने के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिया। बैठक में प्रगतिशील कृषक पारसनाथ सिंह ने किसानों को भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा तथा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा बिहार के अध्ययन भ्रमण पर भेजे जाने का सुझाव दिया। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद के सभी विकास खंडों से कृषकों का चयन कर उन्हें अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाए। जिससे वे आधुनिक कृषि तकनीकों एवं मखाना की उन्नत खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधि

सांड के आतंक से दहशत में थे ग्रामीण, चार घंटे के रेस्क्यू के बाद पकड़ा गया

दैनिक बुद्ध का संदेश

खे सरहा। खे सरहा विकासखंड की ग्राम पंचायत छितही में पिछले कई दिनों से एक खूंखार छुट्टा सांड ग्रामीणों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था। प्रशासन, पशु चिकित्सा विभाग और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से करीब चार घंटे के रेस्क्यू अभियान के बाद सांड को सुरक्षित पकड़कर आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी की गोशाला भेज दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बताया गया कि कुछ दिन पहले इसी सांड ने गांव निवासी गया प्रसाद पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में उनका एक हाथ और सीने की हड्डी टूट गई थी, जिनका उपचार अभी भी जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल था और लोग अकेले निकलने से भी डरने लगे

थे। ग्रामीण हरिशंकर मिश्र ने सांड को पकड़वाने के लिए आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई



थी। पहली शिकायत के निस्तारण के बावजूद सांड गांव में घूमता रहा। दूसरी बार शिकायत दर्ज होने पर प्रशासन सक्रिय हुआ और तत्काल कार्यवाई के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची। पशु चिकित्सक डॉ. अरुण कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। करीब चार घंटे

की कड़ी मशक्कत के बाद सांड को सुरक्षित काबू में कर लिया गया। इसके बाद आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी की कैंटल कैवर टीम ने उसे गोशाला पहुंचाया। ग्राम पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सांड को सुरक्षित गोशाला भेज दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

इस अभियान में शिप्रसाद मिश्र, घनश्याम विश्वकर्मा, मानदेव, परशुराम, बिशम्भर मिश्र, राजकुमार मिश्र, सतीश मिश्र सहित कई ग्रामीणों ने सहयोग किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में घूम रहे अन्य छुट्टा पशुओं को भी जल्द पकड़वाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

सांकेतिक भाषा व स्मार्ट तकनीक से बदलेगी दिव्यांग बच्चों के पढ़ाई के आयाम

दैनिक बुद्ध का संदेश

उसका बाजार। समावेशी शिक्षा शाखा की पहल पर डिजिटल तकनीक अब उन बच्चों के जीवन

के बाद भाषा सबसे बड़ी बाधा बन जाती थी। सामान्य कक्षाओं में कुछ बच्चे पढ़ लेते थे, लेकिन उच्च



में नई रोशनी लेकर आएगी, पढ़ने-लिखने में कठिनाई हो रही थी। इसके माध्यम से एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से साइन लैंग्वेज का वीडियो दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। यह अभिनव प्रयोग सिद्धार्थनगर में पहली बार होने का रहा है। बता दें कि श्रवणबाधित बच्चों के सामने प्राथमिक कक्षाओं

कक्षाओं में साइन लैंग्वेज ही उनके लिए सबसे प्रभावी माध्यम साबित होगी। लंबे समय से इस दिशा में प्रयास तो हो रहे थे, मगर नियमित कक्षा शिक्षण में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी। समग्र शिक्षा के डीसी करुणपति त्रिपाठी ने बताया कि 2025-26 की एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसमें प्रत्येक पाठ के साथ

क्यूआर कोड आधारित साइन लैंग्वेज वीडियो उपलब्ध थे। इस सत्र में लागू करने हेतु समस्त विशेष शिक्षकों को निर्देशित किया गया, उनकी तरफ से समस्त शिक्षकों से भी यह अनुरोध किया जा रहा कि श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यपुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड का उपयोग करें। इससे बच्चों की न केवल वार्ता कोशल बेहतर होगी, बल्कि पाठ्यवस्तु की समझ और परीक्षा परिणाम भी सुधरेंगे। जिले के उन सभी विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी, जहां श्रवणबाधित विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्पेशल एजुकेंटर और विद्यालयी शिक्षक मिलकर स्मार्ट टीवी, टैबलेट व मोबाइल फोन के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर बच्चों को साइन लैंग्वेज वीडियो से पढ़ाएंगे। स्पेशल एजुकेंटर दिव्यांग बच्चों को वीडियो की भाषा सांझाएंगे, फिर शिक्षक प्रतिदिन उसका अभ्यास कराकर अधिगम को मजबूत करेंगे।

खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के दोषी को 10 साल की सजा



सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या—01 सिद्धार्थनगर में हुई। न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने मामले में अभियुक्त आत्माराम लोधी पुत्र स्वर्गीय बाबूराम लोधी निवासी कोटिया पाण्डेय, थाना खेसरहा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्धदंड की सजा सुनाई। मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर चन्द्र, थाना खेसरहा की प्रभावी पैरवी और सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने इसे प्लॉपरेशन कन्विक्शन के तहत एक

दैनिक बुद्ध का संदेश
खेसरहा। प्लॉपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत खेसरहा थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या के एक आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्धदंड से दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वाद संख्या—84 / 2025 एवं मुकदमा अपराध संख्या—234 / 2024, धारा 105 बीएनएस थाना खेसरहा की

फरार वारंटी दुर्गेश मौर्या गिरफ्तार, सोनौली पुलिस ने न्यायालय भेजा।

दैनिक बुद्ध का संदेश
सोनौली / महाराजगंज। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी



के निर्देशन में वारंटियों की गिरतारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोनौली पुलिस ने एक फरार वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार देर रात ग्राम हरदी डाली निवासी दुर्गेश मौर्या (35) पुत्र राजेंद्र मौर्या को उसके आवास से गिरतार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी था और वह काफी समय से गिरतारी से बच रहा था। गिरतार वारंटी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे माननीय न्यायालय, महाराजगंज के समक्ष पेश कर दिया। गिरतारी अभियान में उपनिरीक्षक अभिषेक जायसवाल एवं कांस्टेबल बृजेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि फरार वारंटियों और वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

सम्पादकीय

यदि संपन्न वर्ग, अधिकारियों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते तो शिक्षा जगत में आज व्याप्त गहरी विसंगति की खाई दूर हो जाती। हमारे तंत्र द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति उदासीनता दिखाने, शिक्षकों को गाहे–बगाहे गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने और समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति न करने से ...

तमाम विसंगतियों, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में न होना तथा समय के साथ कदमताल न कर पाने वाले सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोहभंग होना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देशभर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं, छात्रों के प्रवेश व शिक्षकों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले केंद्र के आंकड़ों से पुष्टि हुई कि छात्र सरकारी स्कूलों के विमुख हो रहे हैं और लगातार निजी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीते दो सालों में लगभग 86 लाख छात्र सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। वहीं इसी दौरान प्राइवेट तथा बिना सरकारी मदद वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों में 88 लाख नए छात्र शामिल हुए हैं। ‘यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस’ के अनुसार शुरुआती कक्षा से सेकेंडरी स्तर तक स्कूल में दाखिले में कमी देखी गई है। जो संख्या साल 2023–24 के 24.8 करोड़ से घटकर साल 2025–26 में 24.72 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में दाखिले तेजी से घटकर 12.75 करोड़ से 11.89 करोड़ हो गए हैं। वैसे ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि तमाम कमियों और घटती लोकप्रियता के बावजूद सरकारी स्कूल ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। निस्संदेह, ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिये गंभीर प्रयास किए जाएं। यह हकीकत है कि जमीनी स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि अभी तक अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में सामने आए आंकड़ों का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि सेकेंडरी स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है। वहीं दूसरी ओर शून्य दाखिले वाले स्कूलों की संख्या 12,954 से घटकर 5,663 हो गई है। इसके साथ ही एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1.11 लाख से घटकर 1.01 लाख हो गई है। दूसरी तरफ अब शिक्षकों की कुल संख्या 1.03 करोड़ है, जिसके चलते छात्र–शिक्षक अनुपात 25 से घटकर 24 हो गया है। वहीं लड़कियों की भागीदारी भी बढ़कर 48.4 होना उत्साहवर्धक कहा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा

किया गया है कि स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिये संरचनात्मक सुविधाएं, छात्राओं के लिये शौचालय, हाथ धोने तथा पीने के पानी की व्यवस्था में उत्साहजनक सुधार हुआ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर दावों की हकीकत तार्किक कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सही मायने में किसी सुविधा का उपलब्ध होना और उसका सही तरीके से इस्तेमाल होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन देश के नीति–नियंत्राओं को समझना चाहिए कि समाज में जिस वर्ग को शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, वही सरकारी स्कूलों पर अधिक निर्भर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी अपनी मजबूरी के चलते सरकारी स्कूलों की ओर रुख करता है। इसके बावजूद कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर गाहे–बगाहे सवाल उठाए जाते रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने हर बच्चे को अनिवार्य रूप से निरुशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने को कहा था तो आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में शिक्षा के ये लक्ष्य हासिल क्यों नहीं किए गए? यदि तब केंद्र व राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुध्ारने के लिये ईमानदार प्रयास किए होते और पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराये होते तो आज लोगों को सरकारी स्कूलों से मोहभंग न हो रहा होता। यदि संपन्न वर्ग, अधिकारियों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते तो शिक्षा जगत में आज व्याप्त गहरी विसंगति की खाई दूर हो जाती। हमारे तंत्र द्वारा सरकारी स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति उदासीनता दिखाने, शिक्षकों को गाहे–बगाहे गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने और समय रहते पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति न करने से स्थितियां विकट हुई हैं। यह विडंबना ही कही जाएगी कि सत्तर के दशक में शिक्षा के उन्नयन के लिये गठित कोठारी आयोग की वह सिफारिश आज भी धूल फांक रही है, जिसमें शिक्षा पर देश के जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया था। आर्थिक तंगी से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता व साख पर आंच आई है।

सिंधु की धारा में मौन सिसकी की आहट

इसका सबसे अधिक प्रभाव सिंचाई, पेयजल और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। सिंधु बेसिन पहले ही विश्व के सर्वाधिक जल तनाव वाले नदी तंत्रों में शामिल है, और आगामी दशकों में यह संकट करोड़ों लोगों के अस्तित्व को दांव पर लगा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2025–2034 को ‘क्रायोस्फेरिक साइंसेज के लिए कार्रवाई का दशक’ घोषित किया है। सिंधु के संरक्षण के लिए...

अमरनाथ यात्रा इस समय अपने चरम पर है, लेकिन यात्रा के पहले ही हफ्ते में बर्फानी शिवलिंग के 60 प्रतिशत तक गल जाने के कारण श्रद्धालुओं को भारी निराशा का सामना करना पड़ा है। पवित्र बर्फ़ीले शिवलिंग के नियत समय से पहले गलने की आवृत्ति और तीव्रता पिछले कुछ सालों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। वास्तव में, यह संकट केवल बर्फानी बाबा तक सीमित नहीं है, बल्कि समूचे सिंधु नदी के जल संभरण (कैचमेंट) क्षेत्र में गहराई से पैर पसार चुका है। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की अत्यधिक भीड़, भारी निर्माण कार्यों से उड़ते धूल के गुबार और लाखों की संख्या में दौड़ते वाहनों के प्रदूषण ने इस ऐतिहासिक नदी के अस्तित्व को ही गंभीर संकट में डाल दिया है। सिंधु नदी, जिसने ‘हिंदुस्तान’ और ‘इंडिया’ को वैश्विक पहचान दी और ‘सिंधु घाटी सभ्यता’ को जन्म दिया, आज अपने अस्तित्व के सबसे गंभीर संकट में है। एशिया की यह जीवनदायिनी नदी करोड़ों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा का आधार है। करीब 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह बेसिन ‘थर्ड पोल’ का हिस्सा है। यहां के ग्लेशियर, जो सिंधु के 50 प्रतिशत जल प्रवाह का स्रोत हैं तेजी से सिकुड़ रहे हैं। आईसीआईएमओडी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के बाद इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की गति लगभग दोगुनी हो गई है। वर्ष 1990 से 2020 के बीच इस पूरे क्षेत्र ने अपने ग्लेशियर क्षेत्रफल का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा खो



है। पहले जो हिमपात दिसंबर से फरवरी के बीच होता था, उसका बड़ा हिस्सा अब मार्च और अप्रैल में हो रहा है, जिससे ग्लेशियरों का प्राकृतिक पुनर्भरण लगातार कमजोर हो रहा है। सोनमर्ग से जोजिला दर्रे तक ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी सिंध घाटी धूल और धुएं की एक घनी चादर में लिपट गई हो। पर्यटकों के वाहनों की लंबी कतारें यात्रा की रसद में जुटे बेतहाशा ट्रक, सैन्य बलों के काफिले और मेगा सड़क तथा सुरंग निर्माण परियोजनाओं में लगे भारी अर्थ–मूविंग वाहन प्रतिदिन हजारों की संख्या में इस अत्यंत संकरी और संवेदनशील घाटी से गुजरते हैं। इन वाहनों के पीछे उठते धूल के गुबार और डीजल का काला धुआं हवा के साथ

सीधे ऊपर सदियों पुराने हिमनदों की ओर बढ़ते साफ दिखाई देते हैं। सोनमर्ग के निकटवर्ती थजीवास, मचोई और बालटाल के ऊपरी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियरों की उजली बर्फ़ीली सतह पर मटमैली परत नंगी आंखों से देखी जा सकती है। कदम–कदम पर होने वाले भूस्खलन वाहनों की आवाजाही के दौरान इस धूल को और बढ़ाते हैं। विज्ञान का सीधा–सा नियम है कि स्वच्छ, सफेद बर्फ सूर्य के विकिरण का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, जिसे अलबीडो प्रभाव कहा जाता है। लेकिन जब इसी बर्फ की सतह पर धूल, डीजल वाहनों की कालिख या निर्माण कार्यों से उड़ने वाला ब्लैक कार्बन जम जाता है, तो बर्फ का परावर्तन गुण तेजी से घट जाता है। गहरे रंग की यह परत सूर्य की अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने लगती है, जिससे बर्फ के पिघलने की गति सामान्य से 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक तेज हो जाती है। कश्मीर की सिंद्ी नदी, जो आगे चलकर डेलम और अंततः सिंद्ीु प्रणाली का प्रमुख हिस्सा बनती है, का उद्गम इन्हीं क्षेत्रों में है।

सिंधु बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों विशेषकर लद्दाख, सोनमर्ग और अमरनाथ यात्रा मार्ग में अनियंत्रित पर्यटन ने पर्यावरण पर दबाव डाल दिया है। लद्दाख जैसे शीत मरुस्थल की वहन क्षमता अत्यंत सीमित है, लेकिन वहां प्रतिवर्ष लगभग 5.5 से 6 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं जबकि वहां

की स्थायी आबादी मात्र तीन लाख के आसपास है। पर्यटन के चरम मौसम में प्रतिदिन हजारों डीजल वाहन संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, जिससे न केवल ठोस कचरे और प्लास्टिक का संकट बढ़ा हुआ है, बल्कि जल स्रोतों पर भी दबाव पड़ रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी प्राकृतिक झरनों का जल पूरे वर्ष उपलब्ध रहता था, वहां अब गर्मियों में पानी का संकट दिखाई देने लगा है। अमरनाथ यात्रा निस्संदेह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है, और सामरिक सुरक्षा के लिए ऑल–वेदर कंवेक्टिविटी सुरंगें भी राष्ट्र की प्राथमिकता हैं। लेकिन क्या हिमालय जैसे अत्यंत संवेदनशील और युवा पहाड़ की धारण क्षमता का आकलन किए बिना यह सब अनियंत्रित रूप से होना चाहिए? वैज्ञानिक अब सिंधु नदी के भविष्य को लेकर ‘पीक वाटर’ की अवधारणा की चर्चा कर रहे हैं। शुरुआती दशकों में तेजी से पिघलने के कारण नदी में जल प्रवाह बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी। लेकिन जैसे–जैसे हिमनद पूरी तरह सिकुड़ जाएंगे, जल प्रवाह स्थायी रूप से घटने लगेगा। इसका सबसे अधिाक प्रभाव सिंचाई, पेयजल और खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। सिंधु बेसिन पहले ही विश्व के सर्वाधिक जल तनाव वाले नदी तंत्रों में शामिल है, और आगामी दशकों में यह संकट करोड़ों लोगों के अस्तित्व को दांव पर लगा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2025–2034 को ‘क्रायोस्फेरिक साइंसेज के लिए कार्रवाई का दशक’ घोषित किया है।

बहरहाल, हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पुराना लोकतंत्र भी कहते हैं हम अपने भारत को। सबसे बड़ा या सबसे पुराना होना हमारी विशेषता हो सकती है, पर इससे यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि हमारे लोकतंत्र में कोई कमी नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का यह कहना कि देश के नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है और...



नागरिक का दायित्व और सरकार का कर्तव्य मिलकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को सार्थक बना सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी, उसके अधिकारों का हनन नहीं। शासन भले ही कोई भी चला रहा हो, पर जनतंत्र में असली शासक जनता ही होती है। जनता ही अपने वोट से शासन चलाने का अधिकार देती है या कहना चाहिए अवसर देती है। अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र को परिभाषित करते हुए जनतांत्रिक सरकार को ‘जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा’ बताया था। ऐसे में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से इतनी अपेक्षा तो की ही जानी चाहिए कि वे अपने असली शासक को उचित सम्मान देंगे। जनता को अपने शासकों से यह पूछने का अधिकार है कि वे जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं और यदि ऐसा लगता है कि चुनी हुई सरकार कुछ गलत कर रही है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिाकार जनता को है। सच कहें तो इस तरह की निगरानी रखना जनता का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना

जरूरी है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित शासक राजा नहीं होता, और न ही जनता प्रजा होती है। जनता का यही अधिकार और कर्तव्य उसे चौकीदार की भूमिका निभाने का दायित्व भी देता है। इस चौकीदार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी चुनी हुई सरकार के काम–काज पर नजर रखेगा और यदि कुछ गलत हो रहा है तो न केवल उसे उजागर करेगा, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज भी उठायेगादृ विरोध ा करना, गलत के खिलाफ प्रदर्शन करना हर जागरूक नागरिक का अधिकार है। इस अधिाकार की रक्षा जनतांत्रिक व्यवस्था में जुड़ी सभी संस्थाओं, जिसमें पुलिस प्रमुख है, का कर्तव्य है। पर जब निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं को राजा समझने लगे और पुलिस यह समझने लगे कि वह जनता की नहीं, सरकार की सेवक है तो इसे जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के प्रतिकूल ही माना जायेगा। लेकिन, क्या ऐसा होता है? दुर्भाग्य से इस प्रश्न का उत्तर

नकारात्मक है। हाल ही में यह सवाल मुंबई उच्च न्यायालय के एक कर्तव्यनिष्ठ न्यायाध्ीश ने उठाया था और स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि ‘नागरिकों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सेवक समझना किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता।’ न्यायमूर्ति माधव जामदार एक नागरिक को तडीपार किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाले मामले में टिप्पणी कर रहे थे। नागरिक का अपराध यह था कि उसने सरकार के काम की आलोचना की थी, सरकारी आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया था। न्यायमूर्ति ने पुलिस की इस

विरोध करना जनतंत्र की सार्थकता की पहली शर्त

कार्रवाई की तीव्र आलोचना करते हुए जनतंत्र में नागरिक के अधिकारों का हवाला दिया और कड़े शब्दों में कहा, ‘यह क्या चल रहा है, सारे नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है... ताकि वे विरोध–प्रदर्शन भी न कर सकें!’ जनतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक के पास सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर हथियार यही विरोध–प्रदर्शन करना है और उम्मीद की जाती है कि व्यवस्था नागरिक के इस अधिकार के प्रति सम्मान का भाव रखेगी। आजादी की लड़ाई के दौरान ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को यह अहसास करा दिया था कि आने वाले भारत में नागरिक के पास यही एक कारगर हथियार होगा। संविधान मेंअभिव्यक्ति की आजादी के इस अधिकार को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। सरकार की रीति–नीति के विरुद्ध आवाज उठाना नागरिक का अधिाकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। जब कोई सरकार नागरिक के इस अधिकार पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है तो वह लोकतंत्र को सीमित करने की ही कोशिश समझी जानी चाहिए। इन दिनों देश में ‘कॉकरोच पार्टी’ का आंदोलन चल रहा है। राजधानी दिल्ली में जंतर–मंतर पर देश के युवा अपनी मांगों के समर्थन में पिछले एक पखवाड़े से विरोध–प्रदर्शन कर रहे हैं। वे ‘नीट’ की परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में शिक्षा मंत्री को दोषी मानते हैं और इसीलिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। युवाओं के इस आंदोलन में जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग उन्हें समर्थन भी

दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति लगातार सजग रहने वाले योगेंद्र यादव भी कॉकरोच पार्टी के इस प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे थे। अपने भाषण में उन्होंने लगभग पंद्रह साल पहले इसी जगह हुए भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलन का हवाला देते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि तब भी शुरुआती दौर में आंदोलनकारियों की संख्या तो लगभग आज जैसी ही थी, पर तब जंतर मंतर का यह प्रदर्शन स्थल इतना छोटा नहीं था। उन्होंने कहा, ‘जंतर–मंतर अब छोटा हो गया है’ और यह छोटा होना एक मैदान का क्षेत्रफल कम होना नहीं है, ‘हमारा लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है।’ हमारे लोकतंत्र के सिकुड़ने की यह बात हल्के में लिए जाने की बात नहीं है। सरकार की रीति–नीति पर नजर बनाये रखना और कुछ गलत लग रहा है तो उसका विरोध करना जनतंत्र की सार्थकता की पहली शर्त है। लोकतंत्र के सिकुड़ने का अर्थ है उन मूल्यों और आदर्शों का कमजोर पड़ना जो शासन–प्रणाली को अर्थवान बनाते हैं। लोकतंत्र के सिकुड़ने का यह काम अनायास नहीं

हो रहा, लोकतंत्र को संकुचित किया जा रहा है। दो तरीके हो सकते हैं ऐसा करने केदृ पहला तो यह कि सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को बल प्रयोग करके कमजोर बनाया जाये और दूसरा ऐसे प्रदर्शनों की उपेक्षा करके सत्ता के विरोधियों को हतोत्साहित किया जाये। सरकार यह दोनों तरीके अपनाती है। पांच–छह साल पहले 2020–2021 में किसान आंदोलन को जिस तरह से दबाया गया था, वह देश ने देखा था। यह बात सही है कि तब लगभग एक साल तक चले इस आंदोलन के सामने सरकार को अंततः झुकना पड़ा था, पर जिस तरह किसानों को सरकार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था, वह भी किसी से छिपा नहीं रहा।



स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, अवैध निजी अस्पताल सीज, 8 को नोटिस

दैनिक बुद्ध का संदेश

बहराइच। जनपद के विकास खंड नवाबगंज में स्वास्थ्य



विभाग ने अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों एवं पैथोलॉजी केंद्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय शर्मा के निर्देश पर अधीक्षक डॉ. थानेदार के नेतृत्व में गठित टीम ने विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिना वैध पंजीकरण संचालित एक निजी अस्पताल को तत्काल सीज कर दिया गया। इसके अलावा जांच में अनियमितताएं मिलने पर आठ निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के निजी अस्पताल संचालकों और पैथोलॉजी केंद्रों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण संचालित संस्थानों तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सड़क न बनने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन

दैनिक बुद्ध का संदेश

बहराइच। जनपद के विकास खंड शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा कला के भुर्जिनपुरवा गांव में सड़क निर्माण न होने



से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और जल्द निर्माण की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि लंबे समय से मुख्य मार्ग जर्जर अवस्था में है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में सड़क की स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि मुख्य सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाए। उनका कहना है कि यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

निजी अस्पतालों के बाहर सड़क पर अवैध पार्किंग से रोज लग रहा जाम, राहगीर परेशान

दैनिक बुद्ध का संदेश

बहराइच। शहर में पानी टंकी से डिगिहा तथा डिगिहा तिराहे



से छावनी चौराहे तक स्थित निजी अस्पतालों के सामने सड़क की पटरी पर बड़ी संख्या में बाइक और चार पहिया वाहन खड़े किए जाने से प्रतिदिन जाम की स्थिति बन रही है। इससे आम राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों और तीमारदारों के वाहन सड़क किनारे ही खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे सड़क संकरी हो जाती है। व्यस्त समय में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है और लोगों का समय जाम में फंसकर बर्बाद होता है। कई बार एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। नागरिकों ने प्रशासन और यातायात पुलिस से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि निजी अस्पताल संचालकों को अपने यहां पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए तथा सड़क पर वाहन खड़े होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और आमजन को राहत मिल सके।

बैटरी रिक्शा योजना का इंतजार दिव्यांग की जिंदगी बनी संघर्ष, भीख मांगकर गुजारा करने की मजबूरी

दैनिक बुद्ध का संदेश

नवाबगंज (बहराइच)। सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर



बनाने के लिए बैटरी चालित रिक्शा समेत कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। विकास खंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत नौबस्ता जमुनहा में एक दिव्यांग व्यक्ति आज भी सहायता के अभाव में भीख मांगकर जीवनयापन करने को मजबूर है। मिली जानकारी अनुसार गांव निवासी पागुलिया पुत्र शमशुल ने बैटरी चालित रिक्शा योजना का लाभ पाने के लिए कई बार बाबागंज ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला। दिव्यांगता और आर्थिक तंगी के चलते रोजगार का कोई साधन नहीं है, जिससे रोजमर्रा का जीवन चलाना बेहद कठिन है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई ऐसे दिव्यांग हैं जो सरकारी योजनाओं के पात्र होने के बावजूद लाभ से वंचित हैं। उनका आरोप है कि यदि समय-समय पर सही सर्वे और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई गीजाए तो जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर पाएंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत में विशेष अभियान चलाकर पात्र दिव्यांगों का सर्वे कराया जाए तथा बैटरी चालित रिक्शा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

उतरौला में आज कदीमी शबेदारी का आयोजन, देशभर के धार्मिक विद्वान होंगे शामिल

दैनिक बुद्ध का संदेश

उतरौला / बलरामपुर।

नगर के बड़ा इमामबाड़ा, आबिदा बेगम मोहल्ला, सुभाष नगर में शनिवार 11 जुलाई (25 मोहर्रम) की रात 9 बजे कदीमी शबेदारी एवं शबीह—ए—ताबूत बीमार—ए—कर्बला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रसिद्ध आलिम—ए—दीन, नौहाख्वां और अंजुमन शामिल होकर वाकयाते कर्बला तथा हजरत इमाम सैय्यद सज्जाद की शहादत पर प्रकाश डालें गी। सफीर—ए—अजा सैय्यद अमीर हसन आमिर ने बताया कि कार्यक्रम का संचालन अनीस जायसी करेंगे। हदीस—ए—किसा सैय्यद

अरसलान आरिज पढ़ेंगे, जबकि पेशख्वानी नायाब बलयावी करेंगे। इसके बाद मुंबई से आए मौलाना शाहिद हसन रिजवी मजलिस को संबोधित करेंगे। मजलिस के उपरांत शबीह—ए—ताबूत बीमार—ए—कर्बला बरामद होगा, जिसकी जियारत के बाद विभिन्न अंजुमनों द्वारा मातमी पुर्सा पेश किया जाएगा। कार्यक्रम में अंजुमन जुलफिकारिया (जाजलपुर), अंजुमन हैदरी (हल्लौर), अंजुमन अजा—ए—अहलेबैत सिपाह (जौनपुर) तथा अंजुमन पैगाम—ए—हुसैन अहलेसुन्नत (हलधर मऊ, गांंडा) अपनी प्रस्तुति देंगे। विशेष नौहाख्वानी के लिए

कमाल मेहदी (उत्तराखंड), जहीर अब्बास (मुंबई) और अली वजीर औन (सिवान, बिहार) आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुसैनी अजादार प्रोडक्शन के माध्यम से किया जाएगा, ताकि देश-विदेश के अजादार भी इससे जुड़ सकें। सफीर—ए—अजा सैय्यद अमीर हसन आमिर ने सभी मोमिनीन और अजादारों से समय पर पहुंचकर शबेदारी में शामिल होने तथा शबीह—ए—ताबूत बीमार—ए—कर्बला की जियारत कर सवाब—ए—अजा प्राप्त करने की अपील की है। इस कदीमी शबेदारी के बानी मरहूम इंजीनियर सैय्यद आफताब हुसैन रिजवी रहे हैं।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, 100 वाहनों का किया गया चालान

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। जनपद में सड़क

केवल कानूनी दायित्व ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा

केवल स्वयं का जीवन सुरक्षित रहता है, बल्कि अन्य सड़क



सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनपद में परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा एआरटीओ (प्रशासन) के नेतृत्व में संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात नियमों के प्रति आमजन में जागरुकता बढ़ाना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा। अभियान के दौरान विभिन्न प्रमुख चौराहों, व्यस्त मार्गों एवं संवेदनशील स्थानों पर सघन वाहन चेकिंग की गई। संयुक्त टीम ने अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने,बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन संचालन करने, हाई सिक्वोरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के अभाव, बिना वैध बीमा, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का पालन

से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।इसलिए नियमों की अनदेखी करने वालों के प्रति भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।इस प्रवर्तन अभियान के दौरान कुल 100 वाहनों का चालान किया गया। इसके अतिरिक्त गंभीर अनियमितताएँ पाए जाने पर दोपहिया वाहनों सहित कुल 15 वाहनों को सीज किया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा शराब या अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के बाद वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नियमों का पालन करने से न

किए जाएंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें, सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें तथा वाहन चलाते समय सुख्खा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें। परिवहन विभाग एवं ट्रैफिक पुलिस का यह संयुक्त प्रयास केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रशासन ने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहयोग और नियमों के प्रति जागरुकता से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकेगी तथा जनपद में सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

विश्वकर्मा शिल्पकार पीडीए सम्मेलन, पूर्व मंत्री राम का भव्य स्वागत, 2027 चुनाव को लेकर सपा ने भरी हुंकार

दैनिक बुद्ध का संदेश

श्रावस्ती। हरिहरपुररानी क्षेत्र के बनघूसरा मोड़ पर आयोजित विश्वकर्मा शिल्पकार पीडीए सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा का सपा कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया।

सम्मेलन के दौरान वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों और पीडीए (पिछड़ा, दलित,

अल्पसंख्यक) अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का



आह्वान किया। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार और उसकी नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा

जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है और आम जनता कई समस्याओं से जूझ रही है।

दोना-पत्तल मेकिंग मशीन के चयन हेतु साक्षात्कार 15 जुलाई को

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। जनपद में सरकार

कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला, उत्तराँला रोड, निकट

महाराजगंज पुलिस चौकी, गोण्डा में आयोजित होगा।जिला



ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन कर चुके सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, निवास प्रमाण पत्र

बसपा नेता के.पी. राठौर नजरबंदी से रिहा: पुलिसकर्मी को सौंपा जापन

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मण्डल प्रभारी एवं विधानसभा संयोजक मुस्लिम भाई चारा कमेटी के.पी. राठौर को हरेिया में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का

बेटी की हत्या, मेहनौना में लक्ष्मण निषाद की हत्या, मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के जोगिया में हुई मौत सहित अन्य मामलों को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे। जैसे ही प्रशासन



कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद उन्हें नजरबंदी से मुक्त कर दिया गया। के.पी. राठौर मुख्यमंत्री की जनपद यात्रा के दौरान मिलकर जनपद की समस्याओं, कानून व्यवस्था, ऐथनाल फैक्ट्री, लालगंज के सिद्धनाथ गांव में मासूम दलित

को इसकी जानकारी मिली नगर थाने की पुलिस ने के.पी. राठौर को उनके घर महादेवा विधानसभा क्षेत्र के सिसवारी रघुवीर सिंह में नजरबंद कर लिया। उन्हें मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद छोड़ दिया गया।

अवैध सागौन वृक्षों की कटान पर वन संरक्षक के संज्ञान लेते ही दर्ज हुआ मुकदमा रेन्नाधिकारी का सख्त निर्देश बिना परमिट कटान पर होगी सख्त कार्यवाही

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। वन प्रभाग के अन्तर्गत

क्षेत्राधिकारी सादुल्लाह नगर विजयपाल ने तत्काल मामले

क्षेत्राधिकारी सादुल्लाह नगर के



सादुल्लाह नगर वन रेंज क्षेत्र में लकड़कटो के द्वारा बिना बिना परमिट के अवैध सागौन वृक्षों की कटान के खबर को हिन्दी दैनिक बुध का संदेश अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था,जिसका संज्ञान वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त डॉ.सेम्मरन एम. ने लेकर प्रभागीय वनाधिकारी गोन्डा अनुराग प्रियदर्शी को कार्यवाही का निर्देश दिया था।इसकी क्रम में वन

पर मुकदमा लिखाने के सम्बन्ध में वन दरोगा सुधीर कुमार और फॉरेस्ट गार्ड सुखदेव मिश्रा को मौके पर निरीक्षण करके तथा अवैध तरीके से पातन हुए वृक्षों का बूट तथा अन्य जरूरी कार्यवाही को करके जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।मौके का निरीक्षण करके वन कमियों ने 45 अवैध कटे सागौन वृक्षों की जानकारी दी, जानकारी मिलते ही वन

की प्रतिबंधित वृक्षों के अवैध तरीके से कटान पर कार्यवाही तय है।वन क्षेत्राधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर ठेकेदार बिना परमिट के मनमाने तौर-तरीकों से कटान करेंगे तो विभागीय कार्यवाही के साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। प्रतिबंधित वृक्षों की कटान करने से पूर्व उसका नियमपूर्वक परमिट बनवा लें और कानून कार्यवाही से बचें।

पयागपुर पुलिस का बड़ा खुलासा: चार शातिर चोर गिरतार, सोने-चांदी के जेवर व नकदी बरामद

दैनिक बुद्ध का संदेश

पयागपुर, बहराइच। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पयागपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।



थानाध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चार शातिर चोरों को गिरतार किया है। आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, पीली धातु के जेवर तथा 4,035 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के डिहिया पुल के पास घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरतार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय भेज दिया। गिरतार आरोपियों की पहचान कमलेश चौहान, श्याम उर्फ चौहान, पप्पू उर्फ गोमती चौहान निवासी ग्राम बकवा थाना पयागपुर तथा अजीज उर्फ सद्दाम उर्फ सलीम निवासी थाना कोतवाली नगर, श्रावस्ती के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, चारों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में चोरी समेत कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष दीपक सिंह के साथ उपनिरीक्षक अमित प्रकाश, उपनिरीक्षक रवि कुमार, हेड कांस्टेबल शिवनारायण पाण्डेय, आफताब अहमद, मनीष कुमार तथा कांस्टेबल आशीष चौहान व मनीष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बदहाल स्कूल, बेफिक्र हेडमास्टर! आदर्श बाल विद्यालय में दिखेगा के के मेनन का नया अवतार, पहली झलक संग तय हुई रिलीज डेट



राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है की पूरी कास्ट आई सामने, संजय कपूर के साथ नजर आएंगे ये कलाकार

राघव जुयाल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भाई तेरा स्टार



है को लेकर चर्चाओं में हैं। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया गया था, जिसमें राघव जुयाल नजर आए थे। अब मेकर्स ने फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की घोषणा कर दी है। फिल्म में राघव के साथ एक बड़ी कास्ट नजर आएगी। मेकर्स ने एक दिलचस्प वीडियो के जरिए फिल्म की पूरी कास्ट की जानकारी दी है। इस वीडियो में फिल्म के बाकी कलाकार एक-एक करके आते हैं। अजय सिंह के रोल में राघव जुयाल के साथ इस फिल्म में संजय कपूर, बरखा सिंह, निहारिका एनएम, चंदन रॉय सान्याल, विकल्प मेहता, विवान भट्टेना, निक्की अनेजा वालिया, पार्वती ओमानकुट्टन, टीना देसाई, विनीत बीप कुमार, नासेर अल अजेह और देव बी. अग्रवाल अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। विवेक बी. अग्रवाल द्वारा निर्देशित भाई तेरा स्टार है ईस्टवुड पिक्चर्स और इंडियन स्टोरीज 2 का प्रोडक्शन है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का पहला टीजर जारी किया था, जो दर्शकों को एक ऐसे युवा की मजेदार और उथल-पुथल भरी दुनिया में ले जाता है, जिसे पक्का यकीन है कि वह सुपरस्टार बनेगा। राघव जुयाल इसमें अजय सिंह के मुख्य रोल में हैं। यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

बॉक्स ऑफिस पर अल्फा को जमकर टक्कर दे रही वेलकम टू द जंगल, बेबी डू डाई डू और कॉकटेल 2 की रफ्तार धीमी



सिनेमाघरों में इस समय आलिया भट्ट और शरवरी अभिनीत अल्फा तथा अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर वेलकम टू द जंगल के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। दोनों फिल्में दर्शकों का अच्छा समर्थन हासिल कर रही हैं, हालांकि सप्ताहांत के बाद कमाई की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हुमा कुरैशी की बेबी डू डाई डू अभी तक दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल नहीं हो सकी है। दूसरी ओर कॉकटेल 2 की कमाई अब ६ गिरे-धीरे लाखों तक सिमट गई है। आलिया भट्ट और शरवरी स्टारर अल्फा ने रिलीज के शुरुआती दिनों और पहले वीकेंड में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वीकडेज में इसकी कमाई में उल्लेखनीय गिरावट आई है। बुधवार को फिल्म ने 2.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जो रिलीज के छह दिनों में इसका सबसे कम दैनिक कलेक्शन रहा। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 44.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वहीं 26 जून को रिलीज हुई अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर वेलकम टू द जंगल लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को फिल्म ने 2.35 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 122.90 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म अब भी दर्शकों की पसंद बनी हुई है और टिकट खिड़की पर मजबूती से टिकी हुई है। छोटे बजट में बनी हुमा कुरैशी की बेबी डू डाई डू को अब तक उम्मीद के मुताबिक दर्शक नहीं मिल पाए हैं। रिलीज के छह दिनों में फिल्म एक भी दिन एक करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। बुधवार को इसने 53 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल कलेक्शन 3.11 करोड़ रुपये पहुंच गया। उधर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत कॉकटेल 2 को रिलीज हुए तीन सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। इसके चलते फिल्म की कमाई अब लगातार घट रही है। बुधवार को फिल्म ने 45 लाख रुपये का कारोबार किया। इसके साथ इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 93.90 करोड़ रुपये हो गया है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।

बारिश और व्हाइट कपड़ों की दीवानी हैं मन्नत फेम आयशा सिंह, बोलीं- शूट के बाद भीगने चली गई

टीवी एक्ट्रेस आयशा सिंह इन दिनों अपने सीरियल मन्नतरु हर खुशी पाने की को लेकर सुर्खियों में हैं. शो की कहानी, उनका किरदार और अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आता हैं. इसी बीच



आयशा ने खुलासा किया कि उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद हैं. इतना ही नहीं, उन्हें जब भी मौका मिलता है, वो बारिश में भीगने चली जाती हैं. आयशा ने कहा कि शूट खत्म होते ही मैं बारिश में चली गई. मैंने टीम से पूछा कि क्या मैं भीग सकती हूँ? उन्होंने कहा हां. फिर मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया. बारिश की बूंदें एक अलग सुकून देती है. उनके इस बयान से लगता है कि वो इस मौसम को खुलकर जीती है और अपने दिन को एंजॉय करती हैं. जहां बारिश में कई सेलेब्स को व्हाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद नहीं हैं क्योंकि भीगने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं. वहीं आयशा के ख्याल इससे बिल्कुल अलग हैं और उन्हें इस कलर से कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा, मुझे व्हाइट आउटफिट बहुत पसंद हैं. व्हाइट पे गो क्रेजी. बारिश के साथ व्हाइट कपड़े का कॉम्बिनेशन कैमरे पर सबसे खूबसूरत लगता है. हालांकि आयशा को शॉर्ट्स, टी-शर्ट और पिलप-पलॉप वाला कैजुअल स्टाइल भी बहुत पसंद हैं. वहीं बात करें सीरियल की, तो इसकी शुरुआत पिछले साल जनवरी में हुई, जो कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है. शो की कहानी मन्नत नाम की लड़की की है, जिसका सपना शेफ बनने का है. हालांकि उसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जिससे उसकी जिंदगी बदलती हुई नजर आती है. इसके बावजूद वो हार नहीं मानती और अपने परिवार के लिए खड़ी नजर आती हैं.

एल्युमिनियम बनाम स्टेनलेस स्टील: इन प्रेशर कुर्कर्स में से किसका चयन करना है बेहतर?



प्रेशर कुर्कर्स खाना पकाने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। ये उच्च तापमान और प्रेशर के तहत भोजन को तेजी से पका सकते हैं। हालांकि, जब बात प्रेशर कुर्कर्स की हो, तो बाजार में एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों प्रकार के कुर्कर्स उपलब्ध हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील में से किसका चयन करना अधिक सुरक्षित और लाभकारी है ताकि आप अपने रसोई के लिए सही विकल्प चुन सकें। एल्युमिनियम प्रेशर कुर्कर्स के फायदे एल्युमिनियम प्रेशर कुर्कर्स हल्के होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं, जिससे खाना पकाने का समय कम होता है। ये कुर्कर्स आमतौर पर सस्ते होते हैं और इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। एल्युमिनियम कुर्कर्स अच्छे तापमान वितरण प्रदान करते हैं, जिससे खाना समान रूप से पकता है। हालांकि, इन पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अगर इन्हें तेज आग पर रखा जाए तो ये खराब हो सकते हैं। स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुर्कर्स के लाभ स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुर्कर्स अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। स्टेनलेस स्टील कुर्कर्स में खाना पकाने से कोई हानिकारक रसायन नहीं निकलते, जिससे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये कुर्कर्स साफ करने में भी आसान होते हैं और इनका डिजाइन आकर्षक होता है। स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुर्कर्स में खाना पकाने से पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। सेहत पर प्रभाव जब बात सेहत की आती है, तो स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुर्कर्स अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। एल्युमिनियम कुर्कर्स में कभी-कभी एल्युमिनियम के कण भोजन में मिल सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। स्टेनलेस स्टील कुर्कर्स में खाना पकाने से कोई हानिकारक रसायन नहीं निकलते, जिससे ये सेहत पर कोई असर नहीं डालते। इसलिए अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं तो स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुर्कर्स का चयन करना बेहतर होगा। कीमत और देखभाल पर ध्यान दें कीमत दोनों प्रकार के कुर्कर्स में भिन्नता हो सकती है। एल्युमिनियम कुर्कर्स सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी उम्र कम होती है, वहीं स्टेनलेस स्टील कुर्कर्स महंगे होते हैं, लेकिन इनकी उम्र लंबी होती है और देखभाल भी आसान होता है। अगर आप लंबे समय तक उपयोग करने योग्य कुर्कर चाहते हैं तो स्टेनलेस स्टील कुर्कर्स का चयन करें। हालांकि, अगर आपका बजट सीमित है तो आप एल्युमिनियम कुर्कर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें सुरक्षित रखें। दोनों में से किस प्रेशर कुर्कर का करना चाहिए चयन एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों प्रकार के प्रेशर कुर्कर्स अपने-अपने फायदे और नुकसान रखते हैं। अगर आप सुरक्षित, मजबूत और सेहतमंद विकल्प चाहते हैं तो स्टेनलेस स्टील प्रेशर कुर्कर्स सबसे अच्छा विकल्प होगा। एल्युमिनियम कुर्कर्स सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी उम्र कम होती है और सेहत पर असर डाल सकते हैं। इसलिए अपनी जरूरतों और बजट के अनुसार सही विकल्प चुनें ताकि आप सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से खाना पका सकें।